भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2391

06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि के लिए भूमिगत जल

2391. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महासमुंद लोक सभा क्षेत्र के बसना एवं सरायपाली विकास खण्ड तथा गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खण्ड में सिंचाई के लिए भूमिगत जल उपलब्ध न होने के कारण किसानों को कृषि कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में किसानों के हित में परियोजना का कोई सर्वेक्षण अथवा आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सर्वेक्षण के आधार पर वर्तमान में कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्य किस योजना अथवा एजेंसी के माध्यम से कराए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): देश के गतिशील (डायनामिक) भू-जल संसाधनों का वार्षिक मूल्यांकन केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। नवीनतम (2023) मूल्यांकन के अनुसार

महासमुंद जिले के बसना और सरायपाली विकास खंड तथा गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड के भू-जल संसाधनों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भू-जल संसाधनों का मूल्यांकन	बसना खंड	सरायपाली खंड	देवभोग खंड
1	वार्षिक भू-जल पुनर्भरण(रिचार्ज) (मिलियन घन मीटर)	107.62	86.69	32.40
2	वार्षिक निकाले जाने योग्य भू-जल संसाधन (मिलियन घन मीटर)	96.86	81.58	30.78
3	सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए वार्षिक भू-जल की निकासी (मिलियन घन मीटर)	83.51	41.70	13.72
4	सिंचाई के लिए वार्षिक भू-जल निकासी (मिलियन घन मीटर)	78.93	35.97	11.10
5	भू-जल निकासी का चरण (%)	86.2	51.1	44.6
6	मूल्यांकन इकाई का वर्गीकरण	अर्ध-गंभीर	सुरक्षित	सुरक्षित

इस डेटा से पता चलता है कि बसना में भू-जल निकासी का स्तर 86.2% है, जो यह अर्ध-गंभीर श्रेणी में आता है। सरायपाली में भू-जल निकासी का स्तर 51.1% है, और इसे सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह, देवभोग में भू-जल निकासी का स्तर 44.6% है और इसे भी सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है।

नेशनल एक्वीफायर मैपिंग भू-जल प्रबंधन एवं विनियमन योजना का एक प्रमुख घटक है, जो वर्तमान में जारी एक केंद्रीय योजना है। बसना, सरायपाली और देवभोग खंडों में नेशनल एक्वीफायर मैपिंग अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर भू-जल प्रबंधन योजनाएँ तैयार की गई हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए रिपोर्ट राज्य और जिला अधिकारियों के साथ साझा की गई हैं। जल राज्य का विषय है, इसलिए जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, योजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका उन्हे प्रेरित करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में मौजूदा योजनाओं के संदर्भ में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

*****